गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति

3277. **श्री राघवजी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवंबर, 1991 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार कितनी जनसंख्या **गरीबी** की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है; और

(ख) उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) **गरीबी** की रेखा के नीचे की जनसंख्या के 30 नवंबर, 1991 तक के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1987–88 में **गरीबी** की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या के अनुमान राज्यवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे **देखिए**)

(ख) कृषि, उद्योग तथा सेवाओं इत्यादि के जरिए आय तथा रोजगार सृजन के विकासात्मक प्रयासों के अलावा **गरीबी** उन्मूलन के विशेष कार्यक्रमों को भी चलाया जा रहा है। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या (1987–88)

क्र०सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की सं० (लाख)
1.	आंध्र प्रदेश	195.70
2.	असम	52.89
3.	बिहार	336.54
4.	गुजरात	73.25
5.	हरियाणा	18.15
6.	हिमाचल प्रदेश	4.52
7.	जम्मू व कश्मीर	9.79
8.	कर्नाटक	136.46
9.	केरल	48.98
10.	मध्य प्रदेश	224.97
11.	महाराष्ट्र	214.10
12.	उड़ीसा	135.12
13.	पंजाब	13.88
14.	राजस्थान	99.54
15.	तमिलनाडु	176.85
16.	उत्तर प्रदेश	448.34
17.	पश्चिम बंगाल	173.45
18.	लघु राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	14.2
19.	अखिल भारत	2376.7

टिप्पणी :

1. 1987–88 के लिए अद्यतन **गरीबी** रेखा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 131.80 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 152.13 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है।

2. ये प्राक्कलन घरेलू खपत व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43वें दौर की प्रारूप रिपोर्ट पर आधारित है। (रिपोर्ट सं० 372, "खपत व्यय से संबंधित चौथे पंचवर्षीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट, एन०एस०एस०ओ० जून, 1990)"।

3. गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1988 की जनसंख्या पर आधारित है।

4. राज्यवार गरीबी अनुपात का प्राक्कलन सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय अपनायी गयी पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है। तबसे गरीबी प्राक्कलन की पद्धति के बारे में कई मुद्दे उठाये गए हैं तथा इन मुद्दों पर डा० डी०टी० लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

5. विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत अनुमानों में संशोधन होने की संभावना है।

Plan allocation to States

3278. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has been decided to make the Central plan allocation to State on the basis of population of a State;

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGARMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. Under Modified Gadgil formula, adopted till 1990-91, population, with 60 per cent weightage, and under NDC 'Consensus' formula decided in October, 1990, and adopted during 1991-92 with 55% weightage, was considered the basis for distribution of Central assistance for the states' plan.

(b) and (c) Yes, Sir. Backwardness as a criterion in terms of per capita income, with 20 per cent weightage under Modified Gadgil formula and 25 per cent under NDC 'Consensus' formula for distribution of Central assistance for States' plan has been under operation. Allocation of 20 per cent of total Central assistance was made to the States having per capita income below the national average and 5 per cent which has been added in the NDC formula to all the States on the basis of distance from the highest per capita income.

National Development Council

3279. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that decisions, taken in the meeting of National Development Council, are binding on all the participants; and

(b) if so, the action Government take if any participant fails to abide by the decision taken in the meeting of National Development Council?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGARMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The National Development Council was set up in August, 1952 to strengthen and mobilise the effort and resources of the nation in support of the Five Year Plans, to promote common economic policies in all vital spheres and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country. The decisions taken by the National Development Council are of a collective nature arrived at by consensus.

(b) Does not arise.

Transfer of Central Projects to States

3280. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state: